ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2023; 9(3): 169-172
www.allresearchjournal.com
Received: 29-12-2022
Accepted: 05-02-2023

रंजना कुमारी
शोध छात्र, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, बिहार, भारत

Corresponding Author:
रंजना कुमारी
शोध छात्र, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, बिहार, भारत

कौशल विकास एवं चुनौतियाँ

रंजना कुमारी

सारांश
किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल हैं। मुख्य रूप से कौशल विकास योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं के कौशल के विकास के लिये उन क्षेत्रों में अवसर प्रदान करना है जो कई वर्षों से अविकसित है। 'स्किल इंडिया मिशन' योजना के अन्तर्गत चार अन्य योजनाओं (राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना) को सम्मिलित करके शुरू की गयी है।इस योजना का प्रमुख लक्ष्य यह भी है कि जो प्रतिदिन परिवार के लिए रोटी कमाता है उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाय एवं मौद्रिक पुरस्कार दिया जाय। इस तरह उनके कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।स्किल इंडिया की पॉलिसी में बार–बार बदलाव लाया गया है। इसका परिणाम अच्छा नहीं हो सका है। कई फ्रेंचाइजी सेंटर बंद हो गए हैं। कुशल युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। यह एक बड़ी चुनौती है। करोड़ों युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए करोड़ों रूपए की जरूरत होगी। अतएव एक अच्छा बजट भी चाहिए।स्किल इंडिया के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पहल की है। महिलाओं को बाजार के अनुकूल कौशल विकसित करने के लिए एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन प्रतिबद्ध है।

कूटशब्द : युवा श्रमिक आजीविका कौशल विकास हुनरमंद प्रशिक्षण स्वरोजगार डेमोग्राफिक डिविडेंट उद्यमशीलता

प्रस्तावना
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने स्वप्न 'स्किल इंडिया' को नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' के रूप में शुरू किया। इसमें स्पष्ट किया कि सरकार की गरीबी के खिलाफ एक जंग हैं और भारत का प्रत्येक गरीब और वंचित युवा इस जंग का सिपाही है। इस योजना की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर की थी। साथ ही इस योजना का लोगो (प्रतीक चिन्ह) और टैगलाइन का अनावरण भी किया था।
मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों को शुरू किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत में कौशल विकास योजना कार्यक्रमों की शुरूआत है। 'कौशल भारत–कुशल भारत' की योजना भी इसी का एक भाग है। 'स्किल इंडिया मिशन' योजना के अन्तर्गत चार अन्य योजनाओं (राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना) को सम्मिलित करके शुरू की गयी है।
देश को विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को पूरे भारत में लगभग 40 करोड़ भारतीयों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2022 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 'कुशल भारत–कौशल भारत' योजना को शुरू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उनकी कार्यक्षमता को बढ़ावा देना है। मुख्य रूप से कौशल विकास योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं के कौशल के विकास के लिये उन क्षेत्रों में अवसर प्रदान करना है जो कई वर्षों से अविकसित है। इसके साथ ही साथ विकास करने के नये क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें विकसित करने के प्रयास करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में, 'कौशल विकास योजना, केवल जेब में रूपये भरना ऐसा नही है, बल्कि गरीबों के जीवन को आत्मविश्वास से भरना है।' इस प्रकार इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. गरीबी के कारण जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं उनके अन्दर छिपे कौशल को विकसित करना।
2. योजनाबद्ध तरीके से गरीबों और गरीब नौजवानों को संगठित करके उनके कौशल को सही दिशा में प्रशिक्षित करके गरीबी का उन्मूलन करना।

3. गरीबी को दूर करने के साथ–साथ गरीब लोगों, परिवारों तथा युवाओं में नया सामर्थ्य भरके आगे बढ़ने का आत्मविश्वास लाना तथा देश में नयी ऊर्जा लाने का प्रयास करना।
4. सभी राज्यों और संघ राज्यों को संगठित करके आई.आई.टी. की इकाइयों के मध्यम से दुनिया में स्वयं को स्थापित करना।
5. भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या (जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है) को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिये कौशल एवं अवसर प्रदान करना।
6. देश के युवा और नौजवानों के लिये रोजगार उपलब्ध कराने के लिये उन्हें रोजगार के योग्य बनाने के लिये पूरी एक व्यवस्था के निर्माण को देश की प्राथमिकताओं में शामिल करना।
7. आनेवाले दशकों में पूरी दुनिया में कार्यकुशल जनसंख्या की आवश्यकता को पूरी करने के लिये विश्व के रोजगार बाजार का अध्ययन करके उसके अनुसार देश के युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आज से ही कुशल बनाना।
8. देश के युवा जिस कौशल (जैसे–गाड़ी चलाना, कपड़े सिलना, अच्छी तरह से खाना बनाना, साफ–सफाई करना, मकैनिक का काम करना, बाल काटना आदि) को परंपरागत रूप से जानते हैं, उसके उस कौशल को और निखार कर व प्रशिक्षित करके उस व्यक्ति के कौशल को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करना।
9. कौशल विकास क साथ उद्यमिता और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
10. सभी तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशील बनाना।

किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल हैं। वर्तमान वैश्विक माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती से निपटने में वे देश आगे हैं जिन्होंने कौशल का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में हमारा देश अच्छी स्थिति में है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उत्पादक आयु समूह में है। यह भारत को सुनहरा अवसर प्रदान करता है, परन्तु एक बड़ी चुनौती भी पेश करता है। हमारी अर्थव्यवस्था को इसका लाभ तभी मिलेगा जब हमारी जनसंख्या विशेषकर युवा स्वस्थ, शिक्षित और कुशल होगी।

रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वे न केवल अपने जीवन को प्रभावित करेंगे वरन् दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकेंगे।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल हैं।

नवगठित कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है।

कौशल प्रशिक्षण एनएसडीसी द्वारा हाल ही में संचालित कौशल अंतर अध्ययनों के जरिए मांग के आकलन के आधार पर दिया जाएगा। केन्द्र और राज्य सरकारों, उद्योग और व्यावसायिक घरानों से विचार विमर्श कर भविष्य की मांग का आकलन किया जाएगा। इसके लिए एक मांग समहक मंच भी शुरू किया जा रहा है। कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय ''मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय और ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान'' के मांगों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

कौशल व उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। नवगठित कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की 'मेक इन इंडिया' अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अभियान भारत की एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम् पहल है। विकासशील अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने में इस मंत्रालय की अहम् भूमिका है।

इस दिशा में उठाये गए सभी उपायों को शामिल करने के लिए एक नयी राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति भी तैयार की गयी है। इस नीति के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत ने विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली है। उम्मीद है कि भारत शीघ्र ही विश्व की तीन सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केन्द्र भी बन जाएगा। जनसंख्या के सकारात्मक कारकों और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल की सतत उपलब्धता की मदद से हमारा देश विश्व अर्थव्यवस्था में विशेष छाप छोड़ सकता है।

कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने हेतु कौशल विकास योजना से अवश्य ही हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्ण लाभ मिलेगा। नई नीति के तहत मिशन के तौर पर लागू की गई यह योजना मानव संसाधन और उद्योग के विकास में एक नए युग की शुरूआत करेगी।

भारत में जो कार्यबल है उसका बहुत छोटा–सा हिस्सा को सही मायने में कुशल प्रशिक्षण प्राप्त है। इसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है क्योंकि हमारे यहां जो कार्यबल है, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। उनकी गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब है। कार्यबल की खराब गुणवत्ता का प्रभाव आर्थिक विकास की गति को धीमा कर देता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के मंत्रालय की एक उल्लेखनीय योजना है। स्कीम की पहलकदमी यह है कि लोगों का कौशल विकास हो ताकि उनके कार्य एवं योग्यता को मान्यता मिले। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। कौशल को रोजगारपरक बनाना। कौशल को रोजगार की ओर मोड़ना। कार्य कुशलता में इजाफा करना। इसे विश्वसनीय बनाना। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य यह भी है कि जो प्रतिदिन परिवार के लिए रोटी कमाता है उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाय एवं मौद्रिक पुरस्कार दिया जाय। इस तरह उनके कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

यह कौशल प्रमाणन योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारतीय युवाओं की एक बड़ी संख्या को सशक्त बनाया जाय। इस कार्य के लिए उद्योग प्रासंगिक प्रशिक्षण देना होगा। तत्पश्चात् वे बेहतर आजीविका हासिल करने में सक्षम हो पायेंगे। अतः प्रशिक्षण के कारण नौजवानों में बेहतरी आयेगी और विश्वास आयेगा। जैसाकि हम जानते हैं कि भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात युवाओं का है। यह प्राथमिक उत्पादक मानव संसाधनों का सबसे बड़ा वर्ग है। युवा को सामाजिक और साथ ही आर्थिक विकास में एवं विकास की प्रक्रिया में सीधा योगदान देता है। अतएव यह नौजवानों को समाज के विकास के प्रयासों पर प्राइम फोकस देता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पूर्व शिक्षा अनुभव या कौशल को आकलन करता है। यहां यह बताना जरूरी है कि इस योजना के तहत प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की फीस पूरी तरह सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

हमारे देश के युवाओं का एक बड़ा भाग आजीविका के तलाश में है। आजादी के बाद से ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। लगभग हर साल दस लाख लोग कार्यबल की

श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। आज बहुत बड़ी जवाबदेही है भारत को दुनिया का मानव संसाधन राजधानी बनाने की।

देश की आबादी अभी भी 60 प्रतिशत गांवों में निवास करती है। यह आबादी कृषि पर निर्भर है। सालों भर खेती तो होती नहीं है। अतः कृषि के पश्चात् ये बेरोजगार हो जाते हैं। इसे मौसमी बेरोजगार कह सकते हैं। अतएव कृषक श्रमिक को कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में लगाया जा सकता है। कौशल विकास के पश्चात् इस क्षेत्र से आमदनी की जी सकती है। अपने ही गांव में आसपास इनको रोजगार मिल सकता है। परिणामस्वरूप शहरों की ओर इनका पलायन रूक जायेगा। अतः ग्रामीण शहरी एवं अर्द्धशहरी नवयुवकों को इन उद्योगों से संबंधित कौशल देकर इनको योग्य बनाकर रोजगार या आजीविका साधन उपलब्ध कराया जा रहा है।

भारत इस समय दोराहे पर खड़ा है क्योंकि उसे अपने देश की युवा आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। यूं महत्वाकांक्षी युवा वर्ग और गुणवत्तापूर्ण जीवन की क्षुधा एक विकसित देश के लिए उम्मीदों का शंखनाद भी है। आने वाले 20 वर्षों में औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की श्रमशक्ति में जहां 4 प्रतिशत की गिरावट की आशंका जतायी जा रही है, वहीं भारत में इसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। इन संभावनाशील आयु वर्ग में क्षमता निर्माण करने के लिये केन्द्र सरकार ने भी कई प्रशंसनीय कार्य किए हैं। सरकार देश को विश्वव्यापी मैन्यूफैक्चरिंग हब और कौशल का केन्द्र बनाने का प्रयास कर रही है। कौशल भारत और स्टार्टअप इंडिया मिशन से युवाओं के लिए पढ़ाई के बाद रोजगार प्राप्त करना सहज होगा। साथ ही नए प्रयोगों के लिए उनका मस्तिष्क तैयार होगा। सतत् विकास के लिए यह जरूरी है कि युवा सिर्फ नौकरियां तलाशने का कौशल हासिल न करें– वे नौकरियां देने की मानसिकता भी विकसित करें। यह समावेशी विकास के लिए भी जरूरी है कि युवाओं में उद्यमशीलता की भावना उत्पन्न हो। इसके लिए निरंतर प्रयास और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है। न केवल सरकार, बल्कि निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों को मिलकर काम करना चाहिए और ऐसे नए भारत का सृजन करना चाहिए जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो और उसमें विश्वव्यापी चुनौतियों से निपटने की क्षमता हो।

महत्वाकांक्षी युवा वर्ग में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने की पहल करने की जरूरत है।

स्किल इंडिया मिशन के तहत वर्ष 2016–20 तक एक करोड़ युवाओं को स्किल्ड बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। लेकिन, अभी तक 50 प्रतिशत ही युवाओं को कुशल बनाया जा सका है। बारह हजार करोड़ रूपये इस कार्य के लिए बजट में निर्धारित किया गया है। कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक चालीस करोड़ लोगों को रोजगार पाने लायक स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है।

स्किल इंडिया की पॉलिसी में बार–बार बदलाव लाया गया है। इसका परिणाम अच्छा नहीं हो सका है। कई फ्रेंचाइजी सेंटर बंद हो गए हैं। कुशल युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। यह एक बड़ी चुनौती है।

सेंटर चलाने वाले कई लोगों का आरोप है कि पीएमकेवीवाई के तहत कौशल प्राप्त करने वाले युवाओं में लगभग 57 प्रतिशत का ही प्लेसमेंट हो पाया है। अतएव प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कौशल विकास की चुनौतियाँ

- विद्यार्थियों के बीच कौशल विकास कार्यक्रमों को लेकर सीमित जागरूकता देखा गया। यही कारण है कि कौशल प्रशिक्षण संस्थानों तथा पॉलिटेक्निक में क्षमता के अनुपात में नामांकन कम हुआ है।
- बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान काम नहीं है। अतएव ऋण प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना हुआ जिसका 'रोजगार सृजन' पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है।
- नियोक्ताओं का रवैया कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए सहीं नहीं है। उद्योगों में नियुक्त न करने की इच्छा भी एक बड़ा कारण बनकर उभरा है।
- उद्योगों की सीमित भूमिका के कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण के पश्चात् कम रोजगार का मिलना एवं वेतन का निम्न स्तर होना कौशल विकास के समक्ष चुनौती पेश करता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उनसे यह उम्मीद की जा रही थी कि वे स्वरोजगार की ओर मुड़ेंगे और इसतरह 'रोजगार सृजन' में बढ़ोत्तरी होगी, लेकिन ऐसा हो न सका। केवल 24 प्रतिशत लोगों ने ही अपना व्यवसाय शुरू किया। केवल दस हजार लोगों ने ही 'मुद्रा' ऋण योजना के लिए आवेदन किया।

कौशल प्रशिक्षण और बेरोजगारी

केवल 7 प्रतिशत युवा ही औपचारिक रूप से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त है। युवाओं के बेरोजगारी का यह महत्त्वपूर्ण कारण है। दूसरी बात यह भी है कि युवाओं को जो प्रशिक्षण मिला है, वह अपर्याप्त है एवं गुणवत्ताविहीन है।

आंकड़े यह बताते हैं कि भारत के कुल कार्यबल का 2.3 प्रतिशत ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवा हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक आवश्यक कौशल एवं प्रशिक्षण की कमी है। इसीलिए नियोक्ता को खाली पड़ी रिक्तियों को भरने में कठिनाई हो रही है।

'डेमोग्राफिक डिविडेंट' पर काफी शोर मचा हुआ है। भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया है। विभिन्न मंत्रालयों में चल रही बहुत सारी कौशल विकास योजनाओं को कौशल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत लाया गया है। इससे बिखराव समाप्त हो गया है। कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना और कौशल विकास व उद्यमिता पर भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय नीति' की घोषणा की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में कौशल विकास पर सरकार का फोकस रहेगा।

आईआईटी, आईआईएम, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं चालीस हजार उच्च शिक्षा संस्थानों को कौशल विकास योजना का प्रमुख अंग बनाया गया है। इसके अन्तर्गत 1–6 माह तक का वोकेशनल कोर्स चलाया जा रहा है। इन संस्थाओं के आसपास कई उद्योग भी हैं। अतएव इन संस्थाओं के पड़ोस के उद्योगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि 2022 तक अर्थव्यवस्था के 24 सेक्टरों में 11 करोड़ अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन अग्रलिखित क्षेत्रों में होने वाला है– रीएल एस्टेट, परिवहन, स्वास्थ्य, ब्यूटी पार्लर, रिटेल इत्यादि। 2.5 करोड़ लोग जो कृषि क्षेत्र में हैं, वे गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए गांवों से पलायन कर जाएंगे। पलायन की प्रक्रिया चल रही है। अतएव, ग्रामीण युवाओं को यदि गांव छोड़ने से रोकना है तो समय रहते इन्हें हुनरमंद बनाना होगा एवं रोजगार के योग्य बनाना पड़ेगा, नहीं तो वे पलायन कर जाएंगे और वे पलायन कर रहे हैं। ये अच्छे संकेत नहीं हैं। इससे सामाजिक अस्थिरता पैदा होने वाली है।

मेक इन इण्डिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि राष्ट्रीय स्तर की महत्त्वपूर्ण योजनाएं हैं। इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि युवाओं को प्रशिक्षित करना है और साथ–ही–साथ इनके लिए रोजगार का सृजन भी करना है। युवा श्रम शक्ति को हुनरबंद बनाना है। 2022 तक प्रशिक्षित युवाओं की संख्या लगभग 40 करोड़ होनी चाहिए। यह काम इतना आसान नहीं है।

सरकार के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से सरकार को जूझना होगा।

भारत सरकार संसाधन प्रदान करने वाला देश बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। इस कार्य में हुनरमंद बनाने की महत्वाकांक्षी योजना 'कौशल विकास मिशन' चालीस करोड़ भारतीय युवाओं का भाग्य बदल सकता है। वर्ष 2030 में विकसित देशों में पांच करोड़ नौकरियों के लिए हुनरमंद व प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं की आवश्यकता खड़ी होने वाली है। अतएव भारतीय अप्रशिक्षित युवाओं की पश्चिमी देशों के अनुरूप प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इतना ही नहीं भारतीय युवा श्रमिकों को विशिष्ट हुनर प्राप्त करना होगा। उन्हें विदेशी भाषा, संस्कृषि एवं जलवायु में काम करने में सक्षम होना पड़ेगा। यदि हम अपने युवा श्रमिकों को प्रशिक्षित करने में सक्षम हो पाते हैं तो पांच करोड़ भारतीय युवा पश्चिमी देशों में जाकर काम कर पाएंगे। इसतरह विदेशों में उन्हें नौकरियां मिल जाएंगी। अतएव इस चुनौती को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। अतः 40 करोड़ युवाओं को 2022 तक प्रशिक्षित बनाना असंभव तो नहीं है, लेकिन चुनौतीपूर्ण अवश्य है। यहाँ यह भी गौर करने की जरूरत है कि भविष्य के खतरों से भी सावधान रहना होगा क्योंकि जो हुनर आज प्राप्त किया जा रहा है, हो सकता है, कल उसकी आवश्यकता नहीं रह जाये। आज विभिन्न क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन करोड़ों मौजूदा नौकरियों को निगल जाएंगे। परिणामस्वरूप फिर इनके सामने बेरोजगारी खड़ी हो जाएगी। रातोंरात कोई व्यक्ति कौशल नहीं प्राप्त कर सकता है। अतएव युवाओं को उच्च शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी और नवीनता के साथ जुड़कर रहना होगा। अपने को अपडेट करते रहना पड़ेगा। हमेशा सतर्क एवं सावधान रहने की जरूरत होगी।

अपने देश में सामन्ती प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है। परिणामस्वरूप नियोक्ता एवं श्रमिकों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाता है। कॉन्ट्रेक्ट लेबर के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वही व्यवहार प्रशिक्षित युवा स्वीकार नहीं करेगा, यह तय है। विभिन्न योजनाओं जैसे– मेक इन इण्डिया, कौशल विकास मिशन को सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब प्रशिक्षित युवा को एक इज्जतदार जिंदगी प्राप्त हो।

करोड़ों युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए करोड़ों रूपए की जरूरत होगी। अतएव एक अच्छा बजट भी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा कुशल विकास के प्रशिक्षण पर अपना पैसा तभी खर्च करेगा जब उसे यह बात समझ में आएगी कि उसका रिटर्न उसे सही मिलने वाला है। अर्थात् नियोक्ता द्वारा बेहतर पारिश्रमिक मिलने की संभावना हो। दूसरी चुनौती मिडिल क्लास के सोच को लेकर है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने बच्चों को पलम्बर, हेयर ड्रेसर, ड्राइवर, टेलर, नर्स, कम्पांडर, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन नहीं बनाना चाहता है। वे अपने बच्चों को हुनर की बजाय सामाजिक स्टेटस, आर्थिक सुरक्षा और सम्पन्नता देने वाला पेशों से जोड़ना चाहता है। ऐसी सोंच वाले परिवार के लिए कौशल विकास बेमानी है। ऐसे परिवार के युवा स्किल डेवलपमेंट के बजाय डिग्रियां लेना ज्यादा उपयुक्त समझते हैं। अतएव कई तरह की चुनौतियां हैं।

कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्त्ति के बीच के अंतर को दूर करने, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे का निर्माण करने, कौशल उन्नयन करने, न केवल मौजूदा नौकरियों के लिए बल्कि सृजित की जाने वाली नौकरियों के लिए भी नए कौशलों और नवीन सोंच का निर्माण करने के लिए देशभर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सभी तरह का प्रयत्न करता है।

1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 को मंजूरी दी है। यह नीति सफल कौशल की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी योजना की आवश्यकता को स्वीकार करती है। इस नीति का विजन उच्च मानकों सहित गति के साथ बड़े स्तर पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण की व्यवस्था तैयार करना है तथा उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रूझानों के अनुरूप समीक्षा का भी प्रावधान है। उद्यमिता के क्षेत्र में, नीति में, महिलाओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के दायरे, भीतर एवं बाहर संभावित उद्यमियों को शिक्षित एवं समर्थ बनाने पर जोर दिया गया है।

स्किल इंडिया के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पहल की है। महिलाओं को बाजार के अनुकूल कौशल विकसित करने के लिए एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन प्रतिबद्ध है।

कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रदान किए जाने वाले कौशलों का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य में संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि युवा किसी विशेष कौशल को सीखकर निकले, उसके बाद परिस्थितियों, तकनीक, नवाचार आदि के कारण सिखाए गए कौशल की उपयोगिता खत्म हो जाए। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिजाइन पर नीति निर्धारकों का गहन चिंतन आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. Scheme Document of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, pmkvyofficial, org.
2. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, pmkvyofficial, org. 04-12-2015.
3. Skillindia.gov.in
4. Business Standard, 21 July, 2016.
5. Ibid.
6. Financial Express, 13 July, 2016.
7. सुश्री अर्चना दत्ता – स्वतंत्र लेखिका, पूर्व महानिदेशक, डीडी न्यूज, महानिदेशक, एनएसडी (एआईआर)
8. आलोक कुमार, योजना, मार्च 2017
9. भुवन भास्कर, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2016
10. जतिंदर सिंह, योजना, मई 2017